

दैनिक

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

बेलकम इंडिया

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 263

शुक्रवार, 02 अक्टूबर-2026 (गाजियाबाद)

पेज-8

मूल्य-एक रुपया

पुलिस रिफॉर्म लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकभवन में अत्याधुनिक 87 इंटरसेप्टर वाहनों को प्लैग ऑफ

- 14 लाख से अधिक कैमरों से अपराध पर निगरानी, घटनाओं के खुलासे के साथ रोकथाम में भी मिल रही मदद
- 16 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक, 10 को मुख्यमंत्री वीरता पदक

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकार की कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के हर जिले में दुर्दांत माफिया का बोलबाला था। समानांतर सरकारें चलती थीं। माफिया के सामने नाक रगड़ी जाती थी, घुटने टेके जाते थे और पुलिस मजबूर थी। राजनीतिक नेतृत्व की रीढ़ ही टेढ़ी हो



तो वह कानून-व्यवस्था को सीधा कैसे कर सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लोकभवन सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई, वीर पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह को पुस्तक 'संघर्ष' का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद

सरकार ने पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाया।

प्रकाश सिंह ने जिस पुलिस रिफॉर्म की वकालत की थी, उसे उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे पहले लागू किया। प्रदेश में अब सात पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं। आज यूपी पुलिस के सामने विचार, वीरता और तकनीक, तीनों का समन्वय दिखाई दे रहा है। 'संघर्ष' के माध्यम से पुलिस सेवा के अनुभव और चुनौतियां सामने आई हैं तो जांबाजों की



वीरता का सम्मान हुआ है और सड़क सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन पुलिस बल को समर्पित किए गए हैं।

बंद कमरे में बैठकर टिप्पणी करना बेहद आसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद कमरे में बैठकर किसी के प्रति कोई भी टिप्पणी करना आसान है। कोई व्यक्ति कितना

भी बड़ा क्यों न हो और उसे अपने पद का कितना भी गुरूर हो, सुरक्षा हटा दी जाए तो अराजकता के माहौल में उसे भीगी बिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी। स्वस्थ चिंतन तभी संभव है, जब समाज में सुरक्षा का वातावरण हो। सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। यूपी पुलिस की थीम 'आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प' इसी भावना को व्यक्त करती है। जब तराई क्षेत्र आतंकवाद की

चपेट में था, तब पुलिस व सेना की सुरक्षा में ही आवागमन संभव था। सूर्यास्त के बाद आवाजाही लगभग बंद हो जाती थी।

उस समय डीजीपी के रूप में प्रकाश सिंह ने इन चुनौतियों का सामना किया। पुलिस सुधारों के लिए प्रकाश सिंह को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश ने पुलिस सुधारों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

2017 से पहले कानून-व्यवस्था थी बड़ी चुनौती

मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय 'यूपी वाला' कहकर लोगों को बाहर कर दिया जाता था। पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौतियां थी। राजनीतिक नेतृत्व में स्वयं निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं हो तो कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करना कठिन होता है। तब पुलिस सुधार और अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। एक वर्ष में करीब छह हजार पुलिस कर्मियों को ही प्रशिक्षण दिया जा सकता था। पुलिसकर्मियों को टूटे भवनों में रहना पड़ता था। पीएस की वाहनियां समाप्त कर दी गई थीं। कोसीकलां, मेरठ, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर समेत कई स्थानों पर दंगों के चलते लंबे समय तक कर्फ्यू लगा। इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को बीमाक कहा जाने लगा। अर्थव्यवस्था, रोजगार, तकनीक और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियां खड़ी थीं। 2017 के बाद इन परिस्थितियों को बदलते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया गया।

विचार तभी सार्थक, जब व्यवहार में उतरे

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैचारिकी केवल शब्द या आलेख नहीं होती, बल्कि वह व्यावहारिक जीवन की चुनौतियों को भी समाहित करती है। प्रकाश सिंह ने अपने सेवाकाल में पग-पग पर इन चुनौतियों का सामना किया और अपनी पूरी सेवा को कुशलतापूर्वक पूरा किया। लंबे समय तक विभिन्न संस्थानों में व्याख्यानों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने वाली उनकी वैचारिकी अब पुस्तक के रूप में सामने आई है। आचार और विचार में जब समन्वय होता है और दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तभी परिणाम सामने आता है।

यूपीएससी शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी

युवाओं के भविष्य के लिए समय पर पूरी हों भर्ती परीक्षाएं

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) से कहा है कि वह अपनी परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में चल रहे सुधारों को लागू करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षाओं का युवा उम्मीदवारों के भविष्य पर सीधा असर पड़ता है और चेतावनी दी कि देरी से बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडप में यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए, ढट मोदी ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए और समय की निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए। यह हमारे युवाओं



के भविष्य से जुड़ी है। कुछ महीनों की देरी भी युवाओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है।

इसलिए, परीक्षा प्रणाली को समय की निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यूपीएससी की 100 साल की विरासत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने लाखों युवा भारतीयों के बीच इस संस्था के प्रति अटूट भरोसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज का यह मौका यूपीएससी के 100 साल पूरे

होने और इसकी शानदार विरासत का जश्न मनाने का है। यह जश्न हर साल लाखों युवाओं की उम्मीदों और सपनों को दशाता है। यह जश्न उस भरोसे को भी दिखाता है जो हर भारतीय इस संस्था पर करता है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली एक सदी में पीढ़ियों, सरकारों, टेक्नोलॉजी और सिलेबस में बदलाव के बावजूद वह उभरते हुए लोगों का भरोसा मजबूत बना हुआ है और यह एक बड़ी संपत्ति है।

देश में लागू हुआ मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, देर से दर्ज कराने पर नियम सख्त

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026, 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसमें घटना के एक या दो साल बाद रिपोर्ट किए गए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं।

संशोधित अधिनियम के तहत, घटना के एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर रिपोर्ट किए गए किसी भी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण तभी किया जा सकता है, जब उस इलाके के अधिकार क्षेत्र वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आदेश हो। यह आदेश घटना की सच्चाई की जांच और तय फीस के भुगतान के बाद ही दिया जाता है।

दो साल से ज्यादा देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए, घटना वाली जगह के अधिकार क्षेत्र वाले फर्स्ट



क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है। यह आदेश जन्म या मृत्यु की सच्चाई की पुष्टि होने और लागू फीस का भुगतान करने के बाद ही लिया जा सकता है।

इस संशोधन से 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम' की धारा 13 की उप-धारा (3) में बदलाव किया गया है और एक नई उप-धारा (3अ) जोड़ी गई है।

गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 16 सितंबर, 2026 को एक गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इन प्रावधानों के लागू होने की तारीख 1 अक्टूबर, 2026 तक की गई है।

दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरों से निगरानी, बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा पयूल

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। सड़ियों में होने वाले स्मॉग और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की समस्या से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर, गुरुवार से पूरी राजधानी में 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' का सख्त नियम लागू किया है। नए नियमों के तहत, शहर के सभी पेट्रोल पंप उन गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी नहीं बेच रहे हैं जिनके पास वैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (पीयूसीसी) नहीं है। इस नियम का ठीक से पालन हो, इसके लिए इस पहल में एडवॉरंड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अभियान दिल्ली के लगभग 500 ऐसे फ्यूल स्टेशनों पर चलाया जा रहा है, जहाँ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरा सिस्टम लगे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी फ्यूल भरने वाली नोजल के पास आती है, एएनपीआर कैमरे उसकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी रिकॉर्ड कर लेते हैं और



नेशनल व्हीकल डेटाबेस रिकॉर्ड से उसका मिलान करते हैं। अगर किसी गाड़ी का डबल डबल एक्सपायर हो गया है या नहीं है, तो ऑटोमैटेड सिस्टम फ्यूल भरने की प्रक्रिया को तब तक रोक देता है जब तक कि वैलिड सर्टिफिकेट न मिल जाय।

स्थानीय भारत पेट्रोलियम स्टेशन के मैनेजर दिनेश कुमार ने अटकसे बात करते हुए पुष्टि की कि फ्यूल पंपों पर गुरुवार सुबह से ही सख्ती से नियम लागू कर दिए गए हैं। दिनेश कुमार ने कहा आज सुबह से ही हम किसी भी ऐसी गाड़ी को फ्यूल नहीं दे रहे हैं जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ

पॉल्यूशन सिस्टम को भी लिंक किया गया है, इसलिए अगर सिस्टम दिखाता है कि गाड़ी के पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो मालिक फ्यूल लेने आने से पहले उसे रिन्सु करवा लेता है... अब लोग जागरूक हो गए हैं। आने वाले दिनों में इसका पॉल्यूशन पर असर पड़ेगा क्योंकि सड़ियों का मौसम आ रहा है... यही वजह है कि सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। स्थानीय फ्यूल स्टेशनों पर गाड़ी चलाने वालों और कर्मस्थल ट्रांसपोर्टों ने प्रदूषण रोकने के इस उपाय का काफी हद तक समर्थन किया।

ई-चालान बकाया होने पर नहीं बनेगा पीयूसी, बार-बार नियम तोड़े तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे उन मामलों में ऑनलाइन और वाहन से जुड़ी अन्य सेवाओं को रोक दें, जहाँ ट्रैफिक जुमाना नहीं भरा गया है। इन सेवाओं में रजिस्ट्रेशन का रिन्सुअल, फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (पीयूसी) जारी करना, मालिकाना हक का ट्रांसफर और ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्सुअल भी शामिल है।

यह कदम सड़क सुरक्षा कानूनों के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पालन को और असरदार बनाने की देशव्यापी कोशिश का हिस्सा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि जिन गाड़ियों पर ई-चालान बकाया है, उन्हें सेंट्रल परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि उनकी बिक्री या ट्रांसफर को रोक जा सके।

साथ ही, जब तक ट्रैफिक से जुड़े बकाया जुमाने नहीं भरे जाते, तब तक किसी भी सेंटर को डबल सर्टिफिकेट



जारी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। एक से ज्यादा उल्लंघन के मामलों में, अधिकारियों से कहा गया है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्सुअल को रोक दें और मौजूदा लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए कदम उठाएं। बेंच ने कहा कि हजारों या लाखों ई-चालान जारी करने का तब तक कोई खास फायदा नहीं है, जब तक अधिकारी जुमाना वसूल न कर लें। कोर्ट को बताया गया कि कुछ समय के दौरान जारी किए गए ई-चालान के तहत लगभग 49,194.05 करोड़ बकाया थे, जिनमें से अब तक 26,175.05

करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अधिकारियों को जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर काम करना होगा।

इसमें कहा गया जुमाने वगैरह की वसूली को असरदार ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे उन गाड़ियों को ऑनलाइन सेवाओं को रोक दें जिन पर बकाया राशि है।

अधिकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्सुअल करने या ड्रिलीक्रेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से रोकेंगे और

मालिक का पता वगैरह अपडेट करने की किसी भी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं करेंगे। जब तक सभी पेंडिंग ट्रैफिक जुमाने पूरी तरह से चुका नहीं दिए जाते, तब तक अधिकारी फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे और साथ ही संबंधित गाड़ी को 'परिवहन पोर्टल' पर ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि कई बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्सुअल रोक दिया जाएगा और जो लाइसेंस अभी चालू हैं, उन्हें भी सस्पेंड करने के उपाय किए जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया, 'सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी सेंटर को डबल सर्टिफिकेट जारी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

यह आदेश 2012 के सड़क सुरक्षा मामले में आया है, जिसमें बेंच लगभग 14 सालों से मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को लागू करने की निगरानी कर रही है। जजों ने चिंता जताई कि अगर अधिकारी जमीनी स्तर पर निर्देशों को लागू करने में नाकाम रहते हैं, तो वे निर्देश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह सकते हैं।

यूपी पुलिस एसआई भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा चाबुक!

नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक, आंसर की के 'खेल' से फंसा 12 हजार युवाओं का भविष्य!

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2025 में एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने की तैयारियां चल रही थीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद फिलहाल के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। यह ऐतिहासिक आदेश जस्टिस अनिल कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव और यश पांडे सहित 44 अन्य उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को तक की गई है।

कोर्ट ने नियुक्ति पत्र पर रोक क्यों लगाई है?

ये याचिकाएं अंतिम आंसर की (उत्तर कुंजी) में किए गए बदलावों से संबंधित हैं। वकील संजय कुमार यादव के अनुसार, भर्ती बोर्ड ने 23 मार्च को प्रोविजनल (अर्न्तम) आंसर की जारी की थी, जबकि अंतिम आंसर की 7 मई



यूपी पुलिस एसआई परीक्षा कब हुई थी?

उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस और समकक्ष पदों पर सब-इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन 12 अगस्त, 2025 को जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए 15,75,706 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। परीक्षा में लगभग 10.77 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को घोषित किया गया, जिसमें 12,733 उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य पाए गए। इसके बाद 14 जुलाई को अंतिम परिणाम घोषित किया गया। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी चल रही थी।

को जारी की गई—उसी दिन जिस दिन लिखित परीक्षा का परिणाम आया था। खबरों के अनुसार, अंतिम आंसर की में कई उत्तर बदले गए थे। उम्मीदवारों ने इन बदलावों पर आपत्ति जताई, खासकर इसलिए क्योंकि हर सवाल के लिए 2.5 अंक निर्धारित थे। नतीजतन, कुछ उम्मीदवार जो बहुत कम अंतर से

कट-ऑफ से चूक गए थे, वे इससे प्रभावित हुए। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जो अगले चरण के लिए तो चुने गए थे, लेकिन 14 जुलाई को अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वे सफल नहीं हो पाए। खबरों के अनुसार, कुछ उम्मीदवार सिर्फ एक या दो अंकों से चयन से चूक गए।

सपा सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों को मिलेंगे 51,000 रुपये: अखिलेश यादव



लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय 'भाजपाई आपातकाल' से गुजर रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्गों के खिलाफ अत्याचार और आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई का आरोप लगाया। एक संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने कहा कि जिस अवधि में पीडीए को अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है या कराया जाएगा, उसे आपातकाल कहा जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश ने 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को 'लोकतंत्र सेनानी' बताते हुए कहा कि ऐसे कई लोग बृहस्पतिवार को सपा मुख्यालय में उनसे मिले और अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों के महत्वपूर्ण सुझाव लागू किए जाएंगे।

संपादक की कलम



सीवरेज सफाई: सुरक्षा की कमी क्यों ले रही है जातें?

सीवरेज की सफाई सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरों की स्वच्छता के लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। हर दिन सफाई कर्मचारी ऐसे स्थानों पर काम करते हैं, जिन्हें आम लोग शायद ही कभी देखना चाहते हैं। वे नालियों, सीवर लाइनों और मैनेहोलों की सफाई करके हमारे शहरों को सुचारु और स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन जब पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं होते, तो यही



ललित शर्मा

संपादक

बदल सकती है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और सीवरेज का पानी अचानक बढ़ सकता है। इसलिए सीवरेज सफाई को सामान्य मजदूरी का काम मानकर नहीं चلना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी, उचित तकनीक, जोखिम का आकलन और आपातकालीन तैयारी आवश्यक है। दुर्घटनाएं तब हो सकती हैं जब सुरक्षा प्रक्रियाओं की अनदेखी की जाए, आवश्यक उपकरण उपलब्ध न हों या कर्मचारियों पर काम जल्दी पूरा करने का दबाव हो। कई बार कर्मचारी गैस की जांच, उचित श्वसन सुरक्षा, संचार व्यवस्था या बचाव की तैयारी के बिना ही सीमित स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं। एक और गंभीर समस्या उचित निगरानी की कमी है। किसी बंद या सीमित स्थान में प्रवेश केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होना चाहिए। काम शुरू होने से पहले संभावित खतरों की पहचान, वातावरण की जांच और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी कर्मचारी के प्रवेश से पहले बचाव की योजना तैयार होनी चाहिए। सीवर में किसी व्यक्ति के फंसे पर दूसरा व्यक्ति बिना सुरक्षा व्यवस्था के उसे बचाने के लिए अंदर चला जाता है और स्वयं भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए बचाव का काम प्रशिक्षित कर्मियों और उचित उपकरणों के माध्यम से किया जाना चाहिए। सुरक्षा सुधारने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि जहां संभव हो, मनुष्य को सीवर के अंदर भेजने की आवश्यकता ही कम की जाए। आज यांत्रिक सफाई मशीनें, स्वशन उपकरण, रोबोटिक तकनीक, कैमरा आधारित निरीक्षण और अन्य आधुनिक साधन सीवरेज की सफाई तथा जांच में सहायता कर सकते हैं। ये तकनीकें हर खतरे को समाप्त नहीं करती, लेकिन खतरनाक वातावरण में मनुष्य के सीधे संपर्क को काफी कम कर सकती हैं। तकनीक को सफाई कर्मचारियों के लिए खतरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उनके काम को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने का माध्यम हो सकती है। मशीन ऑपरेटर, रोबोटिक निरीक्षण तकनीशियन, उपकरण विशेषज्ञ और सेंसिटेशन सुपरवाइजर जैसे नए और सुरक्षित कार्यक्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। केवल उपकरण उपलब्ध करा देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। सफाई कर्मचारियों को नियमित और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए। प्रशिक्षण में सीमित स्थानों के खतरों, गैसों की जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, संचार व्यवस्था, आपातकालीन प्रतिक्रिया, प्राथमिक उपचार और मशीनों के सुरक्षित उपयोग जैसी बातें शामिल होनी चाहिए।

आधुनिक ज्ञान

राजेन्द्र लाहिरी पामगढ़ छा

कविता



जात न पूछो साधु की पर उन्हें जात पूछने दो,
पेट पकड़के सोइए उन्हें छप्पन भोग दूस्ने दो,
ये सच है कह गये ज्ञानी क्या है तेरा क्या है मेरा,
है यहां सब कुछ जाति भी तेरा जाति भी मेरा,
कुर्सी की इस दौड़ में कबीर का दोहा भूल गये,
ज्ञान गया अब भाड़ में, सब जाति की म्यान पे झूल गये,
डिग्री-विग्री छोड़िये, पहले अपना गोत्र बताइये,
वरना इस लोकतंत्र में चुपचाप बैठ के कसमसाइए,
वोट बैंक का खेल है, ये अद्भुत चश्मा भाई,
ज्ञान-वान सब गौण है, बस अपनी बिरादरी काम आई,
जो सच कहे वो मूर्ख है, जो जात गिने वो सयाना है,
आधुनिक इस दौर का बस यही एक तराना है,
योग्यता रोती कोने में, और पर्वां यहां बिक जाता है,
नेताजी की रैली में जो जितनी जातियाँ लाता है,
अस्पताल के बेड पर भी अब रिश्तेदारी ढूंढ रहे,
इलाज से पहले लोग यहां अपनी बिरादरी पूछ रहे,
अमृतकाल के दौर में यह कैसा नया सवेरा है,
इंसानियत तो लापता है, बस तेरा-मेरा घेरा है,
साधु-संत भी बदल गये, अब माला नहीं वो सीट गिनें,
तुम भूखे भजन करो प्यारे, वो वोट बैंक की फसल लुनें।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रिन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड, गाजियाबाद- 201001 से मुद्रित करारक ग्राउन्ड प्लोटर, दुर्गा टॉवर, आर.डी. सी राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया।
संपादक : ललित शर्मा
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा।

जनता को सीढ़ी बनाकर स्थापित भ्रष्ट सत्ता नहीं, सेवा को अपना धर्म मानने वाली राजनीति चाहिए



एनके शर्मा

लेखक

लोकतंत्र में सत्ता जनता से निकलती है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जिस जनता की जरूरत पड़ती है, कुर्सी मिलने ही कई बार वही जनता सबसे दूर दिखाई देने लगती है। चुनाव आते हैं तो दरवाजा खटखटते हैं, हाथ जुड़ते हैं, वादे होते हैं, समस्याएं सुनी जाती हैं और जनता को सर्वोच्च बताया जाता है। चुनाव बीतते ही वही नागरिक अपनी शिकायत लेकर दफ्तरो, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटता रह जाता है। यह अंतर केवल राजनीतिक व्यवहार का नहीं, लोकतांत्रिक चरित्र का प्रश्न है।

जनता किसी नेता, दल या सत्ता की सीढ़ी नहीं है। सत्ता जनता की सेवा के लिए बनाया गया सार्वजनिक दायित्व है। जिस राजनीति में जनहित पीछे और सत्ता-प्राप्ति आगे हो जाए, वहां लोकतंत्र का ढांचा तो बचा रह सकता है, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। चुनाव जीतना लोकतंत्र की अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि जनता के

विश्वास की शुरुआत है। असली परीक्षा उसके बाद होती है—क्या प्रतिनिधि जनता के बीच रहता है, उसके प्रश्न सुनता है और अपने निर्णयों का हिसाब देता है?

राजनीति में धनबल का प्रभाव इस परीक्षा को और कठिन बना देता है। जब चुनावी प्रतिस्पर्धा अत्यधिक खचीली होती जाती है, तब सीमित संसाधनों वाला योग्य नागरिक राजनीति से बाहर रह सकता है। यदि आर्थिक सामर्थ्य राजनीतिक प्रभाव का प्रमुख साधन बन जाए, तो लोकतंत्र में समान अवसर का सिद्धांत कमजोर पड़ता है। राजनीति जनसेवा का क्षेत्र है, निवेश पर प्रतिफल प्राप्त करने का कारोबार नहीं। सार्वजनिक पद को निजी प्रभाव, प्रतिष्ठा या आर्थिक लाभ का रास्ता बनने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है।

बाहुबल और भय की राजनीति इससे भी अधिक खतरनाक है। मतदाता का वोट उसकी स्वतंत्र इच्छा का प्रतीक है। किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी या हिंसक प्रभाव उस स्वतंत्रता को चोट पहुंचाता है। लोकतंत्र में विरोधी को डराकर चुप कराना शक्ति नहीं, लोकतांत्रिक कमजोरी का संकेत है। राजनीतिक संघर्ष का मैदान विचारों का होना चाहिए, भय का नहीं; मतभेद का उत्तर तर्क होना चाहिए, दबाव नहीं।

जाति और धर्म हमारे सामाजिक जीवन की वास्तविक पहचानें हैं। उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनका राजनीतिक शोषण स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब नागरिक को उसकी



नीतियों, योग्यता और कार्य के बजाय जातीय या धार्मिक पहचान से देखा जाने लगे, तो लोकतंत्र नागरिकों को व्यक्तियों के रूप में नहीं, वोटों के समूह के रूप में देखने लगता है। यही वह मोड़ है जहां सामाजिक विविधता राजनीतिक विभाजन में बदल सकती है।

किसी नागरिक की जाति उसके अधिकारों की सीमा तय नहीं करती और उसका धर्म उसकी देशभक्ति या राजनीतिक निष्ठा का प्रमाणपत्र नहीं है। राजनीति का काम पहचान मिटाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर पहचान के बावजूद नागरिक को समान सम्मान और अधिकार मिले। समाज को जोड़ने के बजाय चुनावी लाभ के लिए बांटना तत्काल राजनीतिक लाभ दे सकता है, लेकिन उसकी सामाजिक कीमत बहुत लंबी हो सकती है।

सबसे दुखद स्थिति तब पैदा होती है जब जनता की वास्तविक समस्याएं राजनीतिक शोर में दब जाती हैं। बेरोजगार युवा को रोजगार चाहिए, किसान को टिकाऊ आय और बाजार

चाहिए, परिवार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, आम नागरिक को न्याय और सुरक्षित जीवन चाहिए। शहरों को पानी, सड़क, स्वच्छता, परिवहन और प्रदूषण से राहत चाहिए। इन प्रश्नों का समाधान भावनात्मक नारों से नहीं होगा। इनके लिए नीति, बजट, प्रशासनिक क्षमता और निरंतर निगरानी चाहिए।

इसलिए नागरिकों को राजनीति के शब्दों से अधिक उसके परिणामों को देखना होगा। चुनावी घोषणा और वास्तविक उपलब्धि के बीच की दूरी ही असली राजनीतिक रिपोर्ट है। पूछा जाना चाहिए—क्या वादा किया गया था? कितना पूरा हुआ? कितना अधूरा है? सार्वजनिक धन कहाँ खर्च हुआ? निर्णय का लाभ किससे मिला? और यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो जवाबदेही किसकी है?

सवाल पूछना किसी दल का विरोध नहीं है। आलोचना राष्ट्र-विरोध नहीं है। जवाबदेही मांगना लोकतंत्र का अपमान नहीं, उसकी रक्षा है। जिस दिन



जब हमें लगता है कि किसी ने हमारा रास्ता रोका या हमें चुनौती दी, तो दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है। शरीर 'लड़ो या भागो' वाली स्थिति में आ जाता है। एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, दिल की धड़कन और रक्तचाप तेज हो जाते हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं। इस उत्तेजना में सोच-समझकर फैसला लेने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और प्रतिक्रिया आवेग से होने लगती है। यही वजह है कि गुस्से में लोग वह कर बैठते हैं, जिस पर बाद में पछताते हैं। अच्छी बात यह है कि यह उबाल कुछ समय में उतरने लगता है। अगर उन गुस्सेआती पलों में

खुद को रोक लिया जाए, तो अधिकतर विवाद वहीं खत्म हो सकते हैं।

गुस्से पर काबू के छह उपाय

गुस्सा एक सामान्य भावना है। समस्या तब शुरू होती है जब वह हमारे फैसलों पर हावी होने लगे। ड्राइविंग के दौरान कुछ सेकंड का आत्म-नियंत्रण किसी बड़ी दुर्घटना या हिंसा को रोक सकता है।

1. 10 सेकंड रुकिए: गुस्सा बढ़ता लगे तो तुरंत जवाब देने के बजाय गहरी सांस लेकर 10 सेकंड रुकें। खुद से पूछें, 'क्या यह बात 10

नागरिक यह मान लेगा कि चुनाव हुआ प्रतिनिधि प्रश्नों से ऊपर है, उसी दिन लोकतांत्रिक नियंत्रण कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा।

राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। उम्मीदवार का चयन केवल चुनावी गणित, आर्थिक ताकत या सामाजिक प्रभाव से नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आचरण, योग्यता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और जनता के प्रति जवाबदेही भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। राजनीति में अच्छे लोगों के प्रवेश की शिकायत करने से पहले समाज को यह भी देखना होगा कि वह किन लोगों को चुनाव में स्वीकार्यता देता है। मीडिया को भी सत्ता की चमक से अधिक नागरिक के अंधेरे को देखना होगा। पत्रकारिता का काम प्रचार करना नहीं, प्रश्न करना है। सत्ता की उपलब्धियों को तथ्य के साथ प्रस्तुत करना जितना जरूरी है, उसकी विफलताओं की जांच करना भी उतना ही आवश्यक है। स्वतंत्र और तथ्याधारित पत्रकारिता लोकतंत्र की सजावट नहीं, उसकी सुरक्षा-व्यवस्था है। लेकिन राजनीति को बदलने की अंतिम शक्ति राजनीतिक दलों के पास नहीं, जनता के पास है। मतदाता यदि केवल जाति, धर्म, चेहरे, नारों या व्यक्तिगत लाभ के आधार पर निर्णय करेगा, तो राजनीति भी उसी मांग के अनुरूप ढलती जाएगी। राजनीतिक संस्कृति ऊपर से जितनी बनती है, उतनी ही नीचे से भी बनती है। अब नागरिकों को केवल शिकायतकर्ता नहीं, सक्रिय लोकतांत्रिक प्रहरी बनना होगा। अपने

क्षेत्र के प्रतिनिधि के काम का सार्वजनिक रिकॉर्ड मांगें। चुनावी वादों को लिखकर रखें और समय-समय पर उनका हिसाब लें। सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक धन के उपयोग की जानकारी उपलब्ध वैधानिक माध्यमों से प्राप्त करें। स्थानीय निकायों, पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की बैठकों तथा निर्णयों पर नजर रखें। गलत सूचना को आगे बढ़ाने से पहले तथ्य जांचें। जाति और धर्म के नाम पर भड़काऊ संदेशों को राजनीतिक सत्य मानने से इंकार करें। पैसे, उपहार या दबाव के बदले वोट देने की मानसिकता को अस्वीकार करें। और सबसे महत्वपूर्ण—मतदान अवश्य करें, लेकिन मतदान से पहले प्रश्न भी करें। राजनीतिक दलों से भी नागरिकों को पांच स्पष्ट मांगें रखनी चाहिए—उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक हो, चुनावी वित्त में पारदर्शिता हो, आपराधिक मामलों और संपत्ति संबंधी घोषणाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो, जनप्रतिनिधियों के कार्य का नियमित सार्वजनिक लेखा-जोखा हो और जनता से किए गए प्रमुख वादों की प्रगति बताई जाए। यह मांग किसी एक दल के लिए नहीं, हर दल के लिए होनी चाहिए। लोकतंत्र में सिद्धांत व्यक्ति बदलने से नहीं बदलते।

अब समय आ गया है कि नागरिक चुनावी मौसम के दशक बनने के बजाय लोकतंत्र के सक्रिय भागीदार बमें। नेता से पूछें, लेकिन तथ्य के साथ। वादा सुनें, ही नीचे से भी बनती है। अब नागरिकों का सम्मान करें, लेकिन उसे विवेक का विकल्प न बनने दें।

‘इतना गुस्सा क्यों?’ सड़क पर कुछ सेकंड की देरी हमारे शरीर के साथ क्या करती है

मिनट बाद भी इतनी अहम रहेगी?‘ अक्सर जवाब 'नहीं' होगा।

2. बहर जीतने की कोशिश न करें: किसी को गलत साबित करना सुरक्षित घर पहुंचने से ज्यादा जरूरी नहीं है। सामने वाला गुस्से में हो, तो दूरी बनाना ही समझदारी है।

3. हॉर्न और गाली को हथियार न बनाएं: लगातार हॉर्न, गाली, पीछा करना या रास्ता रोकना आग में घी डालता है। शांत प्रतिक्रिया अक्सर विवाद वहीं खत्म कर देती है।

4. शरीर के संकेत पहचानें: तेज धड़कन, कसी मुड़ियां, ऊंची आवाज या शरीर में तनाव, यही रुकने का समय है, जवाब देने का नहीं।

5. कुछ देर के लिए रुक जाएं: लगे कि नियंत्रण छूट रहा है, तो सुरक्षित जगह गाड़ी रोकें। कुछ गहरी सांस लें, पानी पिएं, फिर आगे बढ़ें।

6. बार-बार गुस्सा आए तो मदद लें: छोटी बातों पर बार-बार तेज गुस्सा, चीजें तोड़ने, धमकाने या मारपीट करने का मन होना, इसे 'मेरा स्वभाव ही ऐसा है' कहकर न टालें।

किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या एंगर मैनेजमेंट काउंसलर से बात

करें। अगर कोई आप पर हमला करे या धमकाए, तो गाड़ी के शीशे और दरवाजे बंद रखें, बाहर न निकलें और 112 पर कॉल करें। किसी और के साथ ऐसा होते देखें, तब भी 112 पर सूचना दें।

सड़क सबकी है

सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यहां युवा भी हैं, बुजुर्ग भी; अनुभव की चालक भी और वे भी जिन्हें थोड़ा अधिक समय लगता है। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन एक छोटी गलती को हिंसा में बदलने का फैसला हमारे हाथ में होता है।

हम कार की स्पीड, ब्रेक और इंजन की ताकत पर ध्यान देते हैं। लेकिन ड्राइविंग की एक और क्षमता है, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं पाई जाती। गुस्से पर नियंत्रण।

एक रोज़ कार कुछ सेकंड में रफ़्तार पकड़ लेती है, पर गुस्सा उससे भी तेज बढ़ सकता है।

अच्छी ड्राइविंग का मतलब सिर्फ़ जल्दी मंजिल तक पहुंचना नहीं है। असली ड्राइविंग यह है कि हम मंजिल तक पहुंचें, लेकिन रास्ते में अपना धैर्य, विवेक और ईंसा नियत पीछे न छोड़ें।

छात्र जीवन की चमक के पीछे छिपता मानसिक अंधेरा!



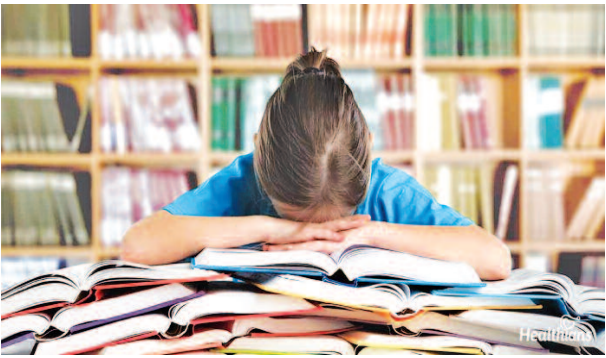
किशन भावनानी

लेखक

वैश्विक स्तर पर आज का डिजिटल युग युवा पीढ़ी के सामने अवसरों का अभूतपूर्व संसार खोल रहा है। छोटे गांव की खेती-किसानी, पारंपरिक दुकानदारी या पारिवारिक व्यवसाय से आगे बढ़कर बड़ी शिक्षा, महानगरों की नौकरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आकर्षण और विदेशों में करियर बनाना आज करोड़ों युवाओं का सपना बन चुका है। गांव से महानगर और भारत से विदेश तक पहुंचने की यह यात्रा आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का प्रतीक दिखाई देती है, लेकिन इसी चमकदार यात्रा के पीछे एक ऐसा प्रश्न भी खड़ा हो रहा है, 'किसे अब नजर अंदाज करना कठिन है, क्या हमारा शिक्षा तंत्र युवाओं को सफल पेशेवर तो बना रहा है, लेकिन मानसिक रूप से सुरक्षित और संतुलित इंसान बनाने में पीछे रह गया है?' मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहता हूं कि 30 सितंबर 2026 के आसपास सामने आए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स (एनटी एफ) ऑन मेन्टल हेल्थ

कॉन्सरन्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रेवेंशन ऑफ सुसाइड्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स के देशव्यापी सर्वेक्षण के प्रारंभिक निष्कर्षों ने इसी प्रश्न को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। मीडिया में सामने आए इन निष्कर्षों के अनुसार 2.43 लाख से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के जवाब सर्वे में शामिल हुए। इनमें लगभग 9 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि पिछले एक वर्ष में उन्हें अक्सर या बहुत अक्सर आत्महत्या के विचार आए, जबकि लगभग 15 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पिछले छह महीनों में कई सप्ताह तक अत्यधिक तनाव, बेचैनी, खराब मनोदशा अथवा चिंता जैसी स्थिति से गुजरने की बात कही। लगभग 34 प्रतिशत विद्यार्थियों ने किसी न किसी स्तर पर अपने परिवार में स्वयं को बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करने की बात भी कही।

साथियों, यहां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे अभी सुप्रीम कोर्ट की अंतिम रिपोर्ट नहीं कहा जाना चाहिए। 29-30 सितंबर 2026 को सामने आए आंकड़े एनटीएफ के सर्वेक्षण के प्रारंभिक/उभरते निष्कर्ष हैं, जिन्हें मीडिया ने रिपोर्ट किया है और जिन्हें अंतिम रिपोर्ट में शामिल किए जाने की उम्मीद है। एनटीएफ ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वे में प्राप्त नमूना देश के सभी छात्र समुदाय का सांख्यिकीय रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए 9 प्रतिशत के आंकड़े को भारत के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों पर सीधे लागू करना उचित नहीं होगा। यही सावधानी इस पूरे विषय को समझने के



लिए अत्यंत आवश्यक है।

साथियों! बात अगर हम एनटीएफ बनी के से और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको समझने की करें तो इस पूरी प्रक्रिया की जड़ 24 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय में है। अमिता कुमार एंड ऑर्डर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डर्स मामले में दो सदस्यीय न्यायमूर्ति की पीठ ने उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के लगातार सामने आने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

आइआईटी दिल्ली सिटी के दो विद्यार्थियों की आत्महत्या से संबंधित था, लेकिन न्यायालय ने इसे केवल एक संस्थान अथवा दो घटनाओं तक सीमित नहीं रखा। न्यायालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य, भेदभाव शैक्षणिक दबाव और कठिनाई, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा पहलक, जातीय अथवा जनजातीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति को सौंपी गई इसमें मनोचिकित्सा नैदानिक मनोविज्ञान, शिक्षा, सामाजिक नीति, दिव्यांगता अधिकार, लैंगिक अध्ययन तथा कानून जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार मूल संरचना में 12 सदस्य तथा 6 पदेन सदस्य थे।

साथियों! बात अगर हम इस टास्क फोर्स का उद्देश्य केवल आत्महत्या के आंकड़े गिनना नहीं है इसको समझने की करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीएफ को व्यापक दायित्व दिया है इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की आत्महत्या के पीछे मौजूद प्रमुख कारणों की पहचान करना, वर्तमान कानूनों एवं संस्थागत व्यवस्थाओं का परीक्षण करना और भविष्य के लिए प्रभावी रोकथाम एवं सहायता प्रणाली की सिफारिश करना है। इसके दायरे में रैगिंग, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, गैर उन्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, आर्थिक कठिनाई, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा पहलक, जातीय अथवा जनजातीय अथवा जनजातीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति को सौंपी गई इसमें मनोचिकित्सा

विषय शामिल हैं। इसलिए 9 प्रतिशत का आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, इसके पीछे यह बड़ा प्रश्न छिपा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को आखिर किस प्रकार का वातावरण मिल रहा है। सर्वेक्षण में लगभग 32 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि उनके संस्थान में परामर्श अर्थात काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि लगभग 56 प्रतिशत विद्यार्थियों ने संस्थान के प्रशासन पर गंभीर मामलों को निष्पक्ष ढंग से संभालने के संबंध में विश्वास व्यक्त किया। लगभग 34 प्रतिशत विद्यार्थियों का परिसर में स्वयं को बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करना भी सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत वातावरण के महत्व की ओर संकेत करता है।

साथियों! बात अगर हम गांव से महानगर और महानगर से विदेश, सफलता की कोमत कितनी? इसको समझने की करें तो, आज एक सामान्य भारतीय परिवार अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी आय का बड़ा हिस्सा उसकी शिक्षा पर खर्च करता है।

गांव का विद्यार्थी पहले जिला मुख्यालय पहुंचता है, फिर किसी महानगर में प्रवेश लेता है और अंततः अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप अथवा किसी अन्य देश में उच्च शिक्षा और रोजगार का सपना देखता है। इस यात्रा में प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, महंगी शिक्षा, छात्रावास जीवन, भाषा की समस्या, परिवार से दूरी, आर्थिक चिंता, सामाजिक तुलना, नौकरी का अनिश्चित

भविष्य और लगातार उकृष्ट प्रदर्शन करने की अपेक्षा जुड़ सकती है समस्या यह नहीं है कि युवा महानगर अथवा विदेश क्यों जाना चाहता है। समस्या तब पैदा होती है जब सफलता की परिभाषा केवल पैकेज, पद, डिग्री विश्वविद्यालय और सामाजिक प्रतिष्ठा तक सीमित हो जाए तथा विद्यार्थी के मन की स्थिति को सफलता का हिस्सा ही न माना जाए। जिस परिवार में बच्चे की परीक्षा के अंक पूछे जाते हैं, लेकिन यह नहीं पूछा जाता कि तुम भीतर से कैसे हो? , वहां शिक्षा अधूरी रह सकती है। जिस संस्थान में उपस्थिति, परीक्षा, रैंक और प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन विद्यार्थी के अकेलेपन, भय और निराशा की नियमित पहचान नहीं होती, वहां मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता दिखाई देती है।

साथियों! बात अगर हम सर्वे का आकार बड़ा है, लेकिन प्रतिनिधित्व की सीमा समझना जरूरी, इसको समझने की करें तो 2.43 लाख से अधिक विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से व्यापक स्तर का डेटा प्रदान करती हैं। इसके साथ ही लगभग 2,119 उच्च शिक्षण संस्थानों ने संस्थागत सर्वे में प्रतिक्रिया दी थी; यह उस समय देश में मौजूद कुल उच्च शिक्षण संस्थानों का लगभग 3.5 प्रतिशत बताया गया था। एनटीएफ ने विद्यार्थियों के अलावा संस्थानों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों से भी जानकारी जुटाई तथा संस्थागत स्तर पर क्षेत्रीय दौरे और परामर्श किए। लेकिन यहीं वैज्ञानिक सावधानी जरूरी है।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, टोली बैठक में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मैदान में उतरने का संदेश

वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। विधानसभा चुनावों को हृष्टित रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर अतिमहत्वपूर्ण टोली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन की तैयारियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला प्रभारी हर्षवर्धन आर्य मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद



मौर्य ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री अनुराग अग्निहोत्री ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी हर्षवर्धन आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव अब करीब हैं। ऐसे में प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी तरह

तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एक टीम के रूप में मिलकर कार्य करना है। बूथ स्तर तक संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और आपसी समन्वय बनाए रखने पर

भी जोर दिया गया। जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा पीलीभीत के कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की

सक्रियता को चुनावी तैयारियों का आधार बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ संगठन के कार्यों में जुटे हुए हैं। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और आपसी तालमेल पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि चुनावी तैयारियों में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दौरान जिला महामंत्री मंगली प्रसाद वर्मा, अनुराग अग्निहोत्री, गुरुभाग सिंह, अभिषेक सिंह गोल्डी, दिनेश पटेल, मनोज गुप्ता, आनुष् मिश्रा, लेखराज भारती, सत्यपाल वर्मा, मानसिंह राठौर, दीपक सोनकर, रेखा सिंह परिहार और नागेंद्र प्रताप सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।



सचिव रामप्रसाद प्रजापति ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं पर समय व आर्थिक भार पड़ता है। उन्होंने क्षेत्र में हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग उठाई। मंडल प्रमुख गुड्डू सैनी ने भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्षेत्र की प्रशासनिक जरूरतों और सुगुलित विकास

को देखते हुए इसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना की मांग भी रखी। इस दौरान महानगर प्रमुख मनोज कुमार, जिला उप प्रमुख हर्षित अग्रवाल, जिला सचिव मोहित रस्तोगी, जिला मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, मंडल सचिव मंगली सैनी, रबेश झा, सुनील सैनी, विनय कश्यप, मुकेश सक्सेना, पंकज प्रजापति, ओम प्रकाश सैनी, अमित चौधरी, सचिन सैनी, जीतू प्रजापति, राहुल प्रजापति समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पीडीए जनपंचायत में कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती का मंत्र राम आसरे विश्वकर्मा की मौजूदगी में हुआ स्वजन संवाद

वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जनपंचायत एवं स्वजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा रहे। अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार ने की, जबकि संचालन विधानसभा बरखेड़ा अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपति गंगवार, सपा जिला उपाध्यक्ष मखदूम खान, धनपति वर्मा एडवोकेट, हरिपाल सिंह लोधी, सपा जिला उपाध्यक्ष बालक राम सागर, रामनरेश वर्मा, सपा जिला उपाध्यक्ष काशीराम सरोज, आशा वर्मा, रामसेनही वर्मा, पिकी पाल, केदारनाथ गौतम, नरेश कुमार सागर और ठाकुर आशीष सिंह चौहान समेत पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता



मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने पीडीए समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों, सामाजिक भागीदारी और संगठन को मजबूत करने को लेकर विचार रखे। पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर

तक मजबूत करने और आम लोगों से संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। धनपति वर्मा एडवोकेट ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता करते हुए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा में भाग लिया और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क तथा आपसी समन्वय को लेकर विचार-विमर्श किया। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी

कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। अंत में संगठन को मजबूत करने, आपसी समन्वय बढ़ाने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

एक शिकायत, दो तस्वीरें: किला थाने पर कार्रवाई नहीं, एसएसपी के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज

वेलकम इंडिया संवाददाता

बरेली। आंटो से उतरते ही महिला को पता चला कि उसका जेवरों से भरा बैग गायब है। बैग में करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर थे। कैमरे चेक हुए तो आंटो और चालक की पहचान हो गई। महिला का आरोप है कि चालक को थाने बुलाने के बाद उससे समझौते के लिए कहा गया और 20-25 हजार रुपये दिलाने की बात कही गई। महिला ने समझौते से इनकार किया तो अगले दिन चालक और आंटो को छोड़ दिया गया। इसके बाद महिला ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर किला पुलिस ने चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। फरीदपुर के कुसुमी गांव निवासी आशा देवी 14 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे सैटेलाइट से आंटो में बैठी थीं। सत्य प्रकाश पार्क के पास किला पुल पर उतरने के बाद उन्हें पता चला कि उनका बैग आंटो में ही

छूट गया है। बैग में सोने का मंगलसूत्र, झुमके, चांदी के कंगन और चांदी की चेन समेत करीब तीन लाख रुपये के जेवर बताए गए हैं। आशा देवी के मुताबिक, वह तुरंत किला थाने पहुंचीं और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने आसपास के कैमरे चेक किए तो आंटो नंबर यूपी-25 सीटी-7734 सामने आया। आंटो चालक की पहचान धारा सिंह पुत्र रामपाल निवासी श्रीधाम कॉलोनी, रामगंगा नगर के रूप में हुई। महिला का आरोप है कि पुलिस ने चालक को थाने बुलाकर पूछताछ की। शुरुआत में चालक बैग के बारे में जानकारी होने से इनकार करता रहा। बाद में उसने 20-25 हजार रुपये देने की बात कही। महिला का आरोप है कि दरोगा कृष्ण कुमार ने भी समझौता करने के लिए कहा और 20-25 हजार रुपये दिलाने की बात कही। महिला ने जेवरों की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताते हुए समझौता करने से इनकार कर दिया।

वेलकम इंडिया संवाददाता

गोरा, पीलीभीत। थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोरा में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की सुविधा के लिए लगाई गई पानी की टंकी लंबे समय से शोपीस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी लगाए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। टंकी तो छत पर दिखाई दे रही है, लेकिन पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन और टोंटी की व्यवस्था नहीं होने से बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले छोटे बच्चों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होना जरूरी है। इसके बावजूद टंकी खाली पड़ी होने से योजना की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी स्तर पर बच्चों की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं तो की जाती हैं, लेकिन



जिम्मेदारों की निगरानी के अभाव में उनका लाभ धरातल तक नहीं पहुंच पाता। ग्रामीणों ने केंद्र के नियमित संचालन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र के मुख्य द्वार पर कई बार ताला लगा दिखाई देता है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता और कई बार निरीक्षण या किसी अधिकारी के आने की सूचना मिलने पर ही ताला

खोला जाता है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गोरा क्षेत्र के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी इसी तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं केंद्र नियमित नहीं खुलने तो कहीं बच्चों की उपस्थिति और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठते हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर निरीक्षण कर

52 ग्राम पंचायतों में होगा 'रिफॉर्म उत्सव', वाटरशेड विकास सुधारों की दी जाएगी जानकारी

बुलंदशहर। वाटरशेड विकास कार्यक्रम को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने और इसमें जनभागीदारी बढ़ाने के लिए जनपद की 52 ग्राम पंचायतों में रिफॉर्म उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह पहल भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जन योजना अभियान-सबकी योजना, सबका विकास के साथ एकीकृत की जा रही है। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2026 से ग्राम सभाओं के माध्यम से होगी। जनपद के बुलंदशहर और अमौता विकासखंडों में संचालित नौ वाटरशेड विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी 52 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को वाटरशेड विकास, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और इससे होने वाले कृषि एवं आजीविका संबंधी लाभों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद राय, जिला और परियोजना स्तर पर भी रिफॉर्म उत्सव की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य वाटरशेड विकास को सरकारी योजना तक सीमित न रखकर जनभागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का रूप देना है।

बाजार गई महिला पर टूट पड़े ससुर-जेठ, मारपीट का आरोप

पूरनपुर/पीलीभीत (वेलकम इंडिया)। पारिवारिक विवाद के चलते लंबे समय से पेशान चल रही एक महिला ने ससुर और जेठ पर बाजार में घेरकर गाली- गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसका विवाह करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था। आरोप है कि पिछले करीब नौ वर्षों से वह अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के व्यवहार से परेशान है। महिला का कहना है कि वह वर्तमान में अपने मायके में रह रही है और अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है। पीड़िता के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे वह अपने पुत्र की किताबें

लेने बाजार जा रही थी। इसी दौरान एक दुकान पर उसके ससुर नसीम हुसैन और जेठ अनवर हुसैन बैठे मिले। आरोप है कि उसे देखते ही दोनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। महिला ने विरोध किया तो मामला और बिगड़ गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अनवर हुसैन ने कथित तौर पर महिला का हाथ पकड़कर उसे दुकान के अंदर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की। विरोध करने पर ससुर और जेठ ने कथित रूप से उसे धमकाया कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसे और उसके पुत्र को जान से मार दिया जाएगा। महिला का आरोप है कि करीब एक साल से उसे घर से बाहर रहने की मजबूर होना पड़ रहा है। उसने पुलिस से आशंका जताई है कि उसके या उसके पुत्र के साथ भविष्य में कोई अग्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी आरोपित लोगों की होगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने समेत तीन मांगों को लेकर शिवसेना ने किया प्रदर्शन

वेलकम इंडिया संवाददाता

मुरादाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा देने, क्षेत्र में एम्स की स्थापना और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर शिवसेना की मुरादाबाद इकाई ने जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी जिला प्रमुख नन्हे चौधरी के नेतृत्व में अबैड कर पार्क से जुलूस की शक्ति में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम तीन सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व शिवसेना जिला प्रमुख नन्हे चौधरी ने किया। शिवसेना राज्य प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में यह प्रदर्शन आयोजित किए जाने की बात पदाधिकारियों ने कही। शिवसेना के प्रदेश

किसानों का जिला मुख्यालय पर हल्लाबोल, 5 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम मांगें नहीं मानी तो सड़क पर उतरेंगे किसान, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर किसान पंचायत की जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना करीब तीन बजे तक चला। किसानों ने प्रशासन के सामने धान खरीद, फसल बीमा, राइस मिलों में कटौती, गन्ना भुगतान, बिजली, आवास, जिला अस्पताल, आवारा पशुओं और मिलावटी खाद्य पदार्थों समेत कई मुद्दे जोरदार ढंग से उठाए। किसान नेताओं ने धान खरीद के लिए तत्काल पंजीकरण शुरू कराने और चार अक्टूबर से सरकारी खरीद व तौल शुरू कराने की मांग की। बेमौसम बारिश से खराब फसलों का उचित मुआवजा देने और छोटी जोत के किसानों को भी क्षति के दायरे में शामिल



करने की मांग उठाई गई। राइस मिलों में नमी मापक यंत्र और धर्मकांटों की जांच कराने तथा किसानों से अनावश्यक कटौती रोकने पर भी जोर दिया गया। गन्ना किसानों के पुराने बकायों का ब्याज सहित भुगतान, घटतौली पर रोक और उतराई वसूली बंद कराने की मांग की गई। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच, बाहर की दवाएं लिखने पर रोक और अस्पताल से आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती बंद करने, बड़े हुए बिजली लोड को ठीक कराने, पात्र गरीबों को आवास दिलाने, अपात्रों की जांच कराने तथा आवारा पशुओं को गोशालाओं में भेजकर फसल क्षति का सर्वे कराने की मांग उठी। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की मांग भी की गई। प्रदेश अध्यक्ष तराई क्षेत्र बलजिंदर सिंह मान, मंडल अध्यक्ष सचिंद्र सिंह कहलौ, प्रदेश सचिव वेद प्रकाश शर्मा

और जिला मीडिया प्रभारी गुरजीत सिंह विक् के किसानों की समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई की मांग की। किसान पंचायत के बाद जिलाधिकारी ने गांधी सभागार में किसान नेताओं और किसानों से वार्ता कर समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। किसान नेताओं ने कहा कि 5 अक्टूबर तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन तेज कर सड़क जाम करने को मजबूर होगा।

सेवा संकल्प अभियान के तहत ब्लॉक सभागार मरौरी में कार्यक्रमों का शुभारंभ

सेवा संकल्प अभियान के तहत ब्लॉक सभागार मरौरी में कार्यक्रमों का शुभारंभ

वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। सेवा संकल्प अभियान के तहत ब्लॉक सभागार मरौरी में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न स्टाॅल लगाए गए, जिनमें टीएलएम का स्टाॅल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। स्टाॅल पर शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के शिक्षण-सहायक सामग्री का प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को रोचक एवं गतिविधि आधारित तरीके से पढ़ाने के प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख सन्ध्या देवी वर्मा एवं खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंह द्वारा प्राथमिक विद्यालय पिपरिया अगरू की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सैयदा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सैयदा को हाल ही में राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास,



नवाचारी शिक्षण, टीएलएम के प्रयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा आरंभिक वातावरण में बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की गई। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सन्ध्या देवी वर्मा ने कहा कि सैयदा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में सैयदा को राष्ट्रपति

पुरस्कार से भी सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों एवं शिक्षकों के प्रयासों की भी सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक समय में बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें गतिविधियों, खेल, टीएलएम, कला एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने के अवसर देना आवश्यक है।

इस दिशा में शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयास बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में लालकरण, बाबू राम गंगवार, देवेंद्र कनैया, इशरत जहां, प्रीति सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक- शिक्षिकाएं एवं बच्चे मौजूद रहे। सभी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

मोदी कॉलेज में पूर्व छात्रों द्वारा छात्रों को मोटिवेशनल व्याख्यान से जागरूक किया गया

सफल होने के लिए सर्वप्रथम संकोच को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकलना होगा: जगदीश गर्ग

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। डॉ. के. एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोदीनगर के पूर्व छात्र ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चीफ जनरल मैनेजर जगदीश प्रसाद गर्ग द्वारा मोदी इंटर कॉलेज अल्युमिनियम संगठन के तत्वावधान में व्याख्यानमाला श्रृंखला के तृतीय लेक्चर कॉलेज में प्रथम पाली के समस्त अध्यापकों एवं छात्रों को सफलता के लिए अनवरत प्रयास विषय को सम्बोधित किया। जिसमें उन्होंने अनवरत प्रयासों की निरन्तरता पर विशेष बल दिया। कैरियर काउंसिलिंग सेंटर के मुख्य समन्वयक संजय गौतम, कैरियर काउंसिलिंग सेंटर के



समन्वयक प्रशांत सांगवान हेड एजुकेशन विभाग शोभित यूनीवर्सिटी ने द्वारा छात्रों को काउंसिलिंग सेंटर पर दर्ज मोबाइल नंबरों पर अपनी आवश्यकता अनुसार संपर्क का सुझाव

किया और व्यक्तिगत रूप से बेझिझक एवं तुरंत अपनी समस्याओं के समाधान पाने में समय व्यर्थ ना करने का सलाह दी। मोदी इंटर कालेज अलयूमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष

राजेश शर्मा, संतोष व्यक्त किया समन्वयकजन संजय गौतम डा प्रशांत सांगवान, कुशल कुमार शर्मा छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही दिशा को पहचानने और उसके अनुरूप सार्थक

परिश्रम सिखाते हैं। प्रधानाचार्य डा.एस सी अग्रवाल ने छात्रों से कहा कैसे आत्मविश्वास की सामर्थ्य और साहस के जादू को मिलाकर चीजों को मुमकिन बनाया जाए। प्रधानाचार्य ने यह भी बताया कि यदि छात्र के अंदर जज्बा जुगुन हो कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। प्रधानाचार्य ने मोदी इंटर कालेज अलयूमनाई एसोसिएशन की भावनाओं का सम्मान करते हुए कालेज प्रबंधन की ओर से पूर्व छात्रों का पटका और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी राज कुमार सिंह, राजीव वर्मा, गौरव त्यागी, डॉक्टर अनीश कुमार जैन, राजीव सिंह पीटीआई, राजीव जागिड़ और समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

‘श्रमदान’ अभियान के तहत सिकरी मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। ‘एक घंटा, एक साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान’ अभियान के अंतर्गत सिकरी मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद मोदीनगर के अध्यक्ष विनोद वैशाली, अधिशासी अधिकारी नरेंद्र मोहन मिश्र एवं सभासदगण दुष्यंत यादव, प्रदीपशर्मा, ललित त्यागी, कृष्णराज सेन सहित नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी एवं अन्य लोगों ने सहभागिता करते हुए मंदिर परिसर में श्रमदान किया और स्वच्छता अभियान को गति प्रदान की।



इस दौरान मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई की गई तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अपने आसपास

के सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने, कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने और स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। अध्यक्ष विनोद वैशाली ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक

प्रयासों से ही मोदीनगर को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतर नगर बनाया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता अभियानों में सक्रिय सहभागिता करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ मोदीनगर झुसुंदर मोदीनगर के संकल्प को मजबूत करते हुए आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार बनने का संदेश दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संचारी रोग एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ



अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोदीनगर पर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले संचारी रोग एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिनेश कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोदीनगर से एक रैली रवाना की गई। जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा आशा कार्यक्रमों उपस्थित रहे। यह रैली सामुदायिक

स्वास्थ्य केंद्र मोदी नगर से प्रारंभ होकर तहसील परिसर में समाप्त हुई। इस रैली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोदीनगर पर तैनात समस्त अधिकारी डॉ. ज्योति डॉक्टर संजय त्यागी डॉक्टर राशिका डॉ. रितु डॉक्टर करणपाल एवं अस्पताल के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। चिकित्सा अधीक्षक मोदीनगर डॉक्टर दिनेश कुमार द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र में इस मौसम में होने वाली बीमारियों का समय रहते संज्ञान लेना तथा उपचार करना है।

खो खो प्रतियोगिता में तुलसीराम माहेश्वरी पी.बी.ए.एस.के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। तुलसीराम माहेश्वरी पी.बी.ए.एस.इंटर कॉलेज मोदीनगर में क्षेत्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें मोदीनगर तहसील के विभिन्न स्कूलों की टीमों ने अंडर 19, 17, 14 आयु वर्ग में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय प्रधानाचार्य श्यामलाल ने किया। उद्घाटन में प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों को आशीर्वाचन देते हुए खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने को कहा साथ ही खिलाड़ियों को मोबाइल खेल से दूर रह कर मैदान में दमखम दिखाने के लिए प्रेरित किया। बालक वर्ग की टीम में अंडर 19 और अंडर 14 आयु वर्ग का



फाइनल तुलसीराम माहेश्वरी पी.बी.ए.एस.इंटर कॉलेज व डा.के.एन.मोदी कॉमर्स एंड साइंस इंटर कॉलेज के मध्य खेला गया। जिसमें पी.बी.ए.एस.इंटर कॉलेज की टीम ने विजय हासिल की। अंडर 17 आयु वर्ग का फाइनल मुकाबला तुलसीराम माहेश्वरी पी.बी.ए.एस.इंटर कॉलेज और एम.डी.इंटर

कॉलेज गोविंदपुरी के मध्य खेला गया। जिसमें पी.बी.ए.एस.इंटर कॉलेज की टीम ने विजयी रही। बालिका वर्ग में अंडर 19 आयु वर्ग में तुलसीराम माहेश्वरी पी.बी.ए.एस.बालिका इंटर कॉलेज की टीम विजयी रही जबकि बालिका अंडर 17 और 14 आयु वर्ग में चमेली देवी दुर्गा प्रसाद बालिका इंटर

कॉलेज सौदा की टीम विजयी रही। प्रतियोगिता का संचालन करते हुए विद्यालय के शारीरिक शिक्षक जयवर्धन सिंह ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी तीन और चार अक्टूबर को इनाहम इंटर कालेज गाजियाबाद में मोदीनगर तहसील का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित कराने में शारीरिक शिक्षक राजीव सिंह, रेखा, संजु कुमार और विद्यालय के एन.सी.सी. अधिकारी कैप्टन रजनीश जिंदल, दीपक कुमार अनिल शर्मा, एस.बी.सिंह, मो.खालिद, पंकज गुप्ता, दीपचंद, वीरेंद्र यादव और पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील, तुषार, हर्ष, यश और लकी का विशेष सहयोग रहा।

भाजपा नेत्री अपराजिता सिंह को प्रदेश अनुसूचित मोर्चा में मीडिया संयोजक बनाया

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। भाजपा नेत्री अपराजिता सिंह को प्रदेश अनुसूचित मोर्चा में मीडिया संयोजक बनाया गया है। अपराजिता सिंह की नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं ने भाजपा हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा नेत्री अपराजिता सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। जानकारी के अनुसार अनुसूचित मोर्चा प्रदेश में एक नियुक्ति महानगर दूसरे गाजियाबाद जिले से एक नाम अपराजिता सिंह का आया है। मोदीनगर की रहने वाली अपराजिता सिंह ने बहुत जल्दी बीजेपी में आने के बाद वह मुकाम पाया है, जो आज



प्रदेश की टीम में उन्हें पद दिया गया। पूरे मोदीनगर के लिए एक सम्मान की बात है। अपराजिता सिंह के नियुक्ति पर क्षेत्र के लोगों ने कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और अपराजिता सिंह को अपनी शुभकामनाएं बधाई दी है।

महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज गोविंदपुरी में हाउस सेरेमनी का भव्य आयोजन

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज गोविंदपुरी, मोदीनगर में विद्यालय की हाउस सेरेमनी का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद मोदीनगर के अध्यक्ष विनोद वैशाली रहे। विद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि का शॉल, पौधा सम्मान प्रतीक भेंट कर स्वागत किया गया।



कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, जिम्मेदारी एवं टीम भावना विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय के हेड बॉय, वाइस हेड बॉय, हाउस कैप्टन एवं वाइस कैप्टन सहित विभिन्न दायित्वों के लिए विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। चयनित विद्यार्थियों को उनके पद एवं दायित्व की शपथ दिलाई गई तथा विद्यालय की गरिमा बनाए रखने और

अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। विनोद वैशाली ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालयी जीवन में नेतृत्व की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण अवसर है। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. अंशु सिंह ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हाउस व्यवस्था विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी

की भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह एवं उमंग देखने को मिली। हाउस कैप्टन एवं वाइस कैप्टन ने अपने-अपने हाउस को अनुशासन, एकता और उत्कृष्ट प्रदर्शन की दिशा में आगे ले जाने का संकल्प लिया। मंच का संचालन विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता रवि भूषण गौतम ने किया गत वर्ष के विनर हाउस आर्यभट्ट को भी सम्मानित किया गया।

विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से किया संवाद



अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के भोजपुर ब्लॉक में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आंगन मिलन कार्यक्रम में विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने उपस्थित होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से संवाद किया। विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने आंगनवाड़ी बहनों द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों की जानकारी प्राप्त की तथा उनके अनुभवों, सुझावों एवं कार्यक्षेत्र से जुड़ी आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज के सबसे महत्वपूर्ण

आधारभूत स्तर पर बच्चों, महिलाओं एवं परिवारों तक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं एवं कल्याणकारी प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने आंगनवाड़ी बहनों के समर्पण एवं सेवाभाव की सराहना करते हुए कहा कि उनके सतत प्रयासों से समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रिया-व्ययन सुनिश्चित हो रहा है।

आईपीईसी में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से रोपे पौधे

पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का दिया संदेश, छात्र-शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज (आईपीईसी) में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।



भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से आयोजित अभियान में कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एजीएम फाइनैस राजेन्द्रन श्रीनिवास, सीनियर डीजीएम क्यूएस सुभाष नायक, आईपीईसी के वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल, निदेशक आकांक्षा अग्रवाल, आईसीएआई के वाइस प्रेसिडेंट मनोज कुमार आनंद, सीएमए शिवम शर्मा,

कैप्टन डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) डीके शर्मा और डीन एके डमिकस प्रो. (डॉ.) अमित जैन ने पौधारोपण कर किया। इस दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अभियान के तहत कॉलेज परिसर के विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों में देशज प्रजातियों के पौधे लगाए गए। विभागाध्यक्षों, फैकल्टी सदस्यों, संस्थागत कर्मचारियों और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण और देखभाल

का संकल्प भी लिया। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की संयुक्त पहल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें सतत विकास और हरित भविष्य के प्रति जागरूक किया गया।

सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की पहल, बाबा इंटरनेशनल स्कूल में जागरूक हुए छात्र



गाजियाबाद। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को बाबा इंटरनेशनल स्कूल में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर पुलिस उपरुक्त (यातायात) के निदेशन में यातायात निरीक्षक जोन-09 ने छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ को यातायात नियमों और विभिन्न यातायात संकेतों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

गिन्नी देवी मोदी कॉलेज में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन



अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स पीजी कॉलेज मोदीनगर में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए अभिबन्धन कार्यक्रम का आयोजन राजनीतिक विज्ञान विभाग तथा इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पूनम शर्मा ने की। प्राचार्या ने छात्राओं का महाविद्यालय परिवार की ओर स्वागत

कर उन्हें युनिफार्म पहनकर आने तथा मोबाइल के बंदूते दुरुपयोग, साइबर अपराध से सावधान रहने के कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। राजनीतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. नूतन सिंह ने छात्राओं को नवीन शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों से परिचित कराया तथा स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय एवम् कौशल विकास कार्यक्रम के विषय मे विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम मे कम्प्यूटर विभाग व कौशल विकास प्रभारी अनीता सिंह व

शिवानी शर्मा का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम मे डॉ. आकांक्षा सारस्वत, ऐश्वर्य बहुगुणा, मंजू कन्नौजिया, शालू त्रिवारी, गार्गी, खुशबू, गीता त्यागी, अनीता कौशिक, रूबी, सारिका त्यागी, ऋतु शर्मा, सुमन, आदि ने प्रतिभागिता की। सेवा संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत आज नयी राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की वर्तमान में आवश्यक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन नोडल अधिकारी रश्मि चौधरी के द्वारा किया गया।

डेंगू-मलेरिया के खिलाफ निकली जागरूकता रैली, फॉगिंग मशीनों ने भी संभाला मोर्चा

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। संचारी रोगों की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। संयुक्त जिला चिकित्सालय, संजय नगर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। अभियान एक से 31 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दस्तक अभियान 12 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा। रैली में नगर निगम की करीब 100 छोटी-बड़ी फॉगिंग मशीनों के अलावा 10 स्प्रिकलर और पांच पावर स्प्रेयर मशीनों ने भी भाग लिया। जिला मलेरिया अधिकारी जीके मिश्रा ने लोगों से डेंगू समेत अन्य संचारी रोगों से बचाव के लिए सावधानी बरतने, घरों के आसपास पानी जमाने होने देने



और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की।

मुख्य विकास अधिकारी ने रैली में शामिल स्कूली बच्चों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मोमेंटो

देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सिविल डिफेंस, पशुपालन विभाग, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग, डब्ल्यूएचओ, मलेरिया विभाग, आईडीएसपी यूनिट और

विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि व छात्र-छात्राएं शामिल रहे। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता समेत चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा।

गाजियाबाद नगर निगम में 'सुपर स्कैम' का सनसनीखेज खुलासा

रिश्वतखोरी, उगाही और फर्जीवाड़ा का बड़ा नेटवर्क, तंत्र में हड़कंप!

ललित शर्मा

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। नगर निगम का मोहन नगर जोन इन दिनों भ्रष्टाचार के भीषण चक्रव्यूह और घुसखोरी के संगीन आरोपों से थरा उठा है। निगम के बेदाग छवि वाले एक स्थाई सफाई नायक द्वारा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई एक विस्तृत और शिकायती चिट्ठी ने नगर निगम के शीर्ष गलियारों में मानो भूचाल ला दिया है। पीड़ित कर्मचारी का दावा है कि निगम के कतिपय आला अधिकारियों और उनके मातहतों ने मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट बना रखा है, जो हर महीने लाखों रुपये की संगठित वसूली (रंगदारी/घूस) कर रहा है और सच बोलने वालों को झूठे मुकदमों और



निलंबन की धमकी देकर बलि का बकरा बना रहा है।

डंडे के बल पर कबूलनामा और फर्जी निलंबन का साजिश रचने का आरोप

पत्र में आरोप लगाया गया है कि 9 फरवरी 2025 को डीजल चोरी का एक फर्जी वीडियो वायरल होने का बहाना बनाकर कर्मचारी को नगर निगम दफ्तर तलब किया गया। आरोप है कि अपर नगर आयुक्त के कमरे में चपरासी से डंडा मंगवाकर, जेल भेजने

मासिक 'हफ्ता' और 'मलाईदार' पोस्टिंग का खेल

शिकायतकर्ता स्थाई सफाई नायक संजय कुमार के पत्र के अनुसार, मोहन नगर स्वास्थ्य गैराज में पूरी ईमानदारी से काम करने के बावजूद डाक्टर मिथिलेश कुमार (जिनकी एक ही स्थान पर 10 वर्षों से अधिक की लंबी तैनाती है) ने उनका जबरन स्थानांतरण कर दिया। इसके बाद कंप्यूटर डीजल पंप पर दोबारा तैनाती देने के नाम पर उनसे 60,000 रुपये की एकमुश्त घूस ली गई। आरोप है कि इसके बाद हर महीने 1,00,000 रुपये डाक्टर मिथिलेश के नाम पर वसूले जाने लगे। इतना ही नहीं, शिकायती पत्र में नामजद अधिकारियों की जो सूची दी गई है, उसने पूरे निगम प्रशासनिक ढांचे को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

अपर नगर आयुक्त अमर्नंद यादव: कथित तौर पर 30,000 रुपये प्रति माह की वसूली अपने कारिंदे के जरिए।
ZSO ओगण्डाल: 30,000 रुपये प्रति माह का नियमित कट।
डीजल पंप लिफ्टिंग महेंद्र प्रताप उर्फ मोटी: 1,00,000 रुपये प्रति माह की भारी भरकम उगाही।

जांच में नहीं मिला एक लीटर भी कम डीजल: गाड़ियों के नाम पर 2-2 लाख की वसूली

मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जांच टीम ने कंप्यूटर डीजल पंप के टैंक, चालकों की लॉग बुक और डीजल मेटेनेंस रजिस्टर का मिलान किया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पंप से एक लीटर भी तेल चोरी नहीं हुआ था, आरोप है कि यह पूरी साजिश मोहन नगर गैराज और कंप्यूटर पंप पर अपने चहेते (अशोक मखवाना व अमरजीत) को तैनात करने के लिए रची गई थी। शिकायती पत्र के मुताबिक, अमरजीत नामक कर्मचारी के जरिए ड्राइवरों को नई गाड़ियां आवंटित करने के नाम पर 2-2 लाख रुपये की अवैध वसूली की जा रही है।

गाजियाबाद के पूर्व डीसीपी निपुण अग्रवाल को राष्ट्रपति वीरता पदक मिलने पर संजीव कुमार गुप्ता ने बधाई दी

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस के होनहार आईपीएस अधिकारी और गाजियाबाद में डीसीपी सिटी के पद पर रहे निपुण अग्रवाल को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए राष््र पति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में आयोजित एक गरिमायय सम्मान समारोह में उन्हें यह



पदक प्रदान किया। संजीव कुमार गुप्ता जी ने आईपीएस निपुण अग्रवाल को इस गौरवपूर्ण सम्मान के लिए हार्दिक बधाई एवं

शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि निपुण अग्रवाल जैसे निडर और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों पर पूरे देश को गर्व है। उनका यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस के शौर्य का प्रतीक है।

राजनगर एक्सटेंशन से लापता डॉक्टर का ईस्टर्न पेरीफेरल पर मिला शव, ओवरडोज की आशंका



वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन से लापता 30 वर्षीय डॉक्टर शिवम कार्तिकेय का शव बुधवार को मुरादनगर क्षेत्र में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर खड़ी बेजा कार से बरामद हुआ। कार काफ़ी देर से एक ही स्थान पर खड़ी होने की सूचना पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। कार की तलाशी लेने पर अंदर डॉक्टर का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक की पहचान डॉ. शिवम कार्तिकेय पुत्र गोपाल स्वरूप,

निवासी वीवीआईपी मंगल सोसाइटी, राजनगर एक्सटेंशन के रूप में हुई है। परिजनों ने 29 सितंबर को नंदग्राम थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार कार से कई इंजेक्शन और दवाइयां बरामद हुई हैं।

प्रथमदृष्टया शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। एसीपी मुरादनगर सुनील कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

दिल्ली-हापुड़ रोड के फुटओवर ब्रिज पर मिला अज्ञात शव, मचा हड़कंप

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। वेवसिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली-हापुड़ रोड स्थित फुटओवर ब्रिज पर गुरुवार सुबह अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 8:40 बजे पीआरवी के माध्यम से पुलिस को फुटओवर ब्रिज पर शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वेवसिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की

फुटेज खंगाल रही है, ताकि मृतक की पहचान होने के साथ ही उसकी मौत से जुड़े तथ्यों का भी पता लगाया जा सके।



पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने बुधवार को चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक स्नेचर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, 5/6 पुलिया रोड पर संधिध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।

इसी दौरान कनानवी पुलिस की ओर से बाइक सवार एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।



पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया।

घायल आरोपी की पहचान मुनासिर उर्फ मुनासिर पुत्र मोईन अहमद, निवासी



गरिमा गार्डन, साहिबाबाद के रूप में हुई। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, 315 बोर का

अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा पीली धातु का एक टुकड़ा बरामद किया है। पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जनसुनवाई में डीएम ने सुनीं फरियादें, अफसरों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश



वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडड़ ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। राजस्व, बिजली, नगर निकाय, पुलिस, भूमि विवाद, पेंशन और राशन समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखी गईं। डीएम ने संबंधित

विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण कर फरियादियों को प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की निर्यामित समीक्षा की जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम करने को कहा। जनसुनवाई में एडीएम एल/ए, एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सीआरपीएफ जवानों, पुलिसकर्मियों और छात्रों ने चलाया स्वच्छता अभियान

कपिल चौहान

ग्रेटर नोएडा (वेलकम इंडिया)। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' अभियान के तहत सीआरपीएफ के जवानों, यूपी पुलिस के जवानों और केन्द्रीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अभियान के दौरान जवानों और विद्यार्थियों ने विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर दायरी विधायक तेजपाल नागर भी कार्यक्रम में पहुंचे और स्वच्छता अभियान में भागीदारी करते हुए लोगों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने 'स्वच्छता ही सेवा-2026' का संदेश देते हुए स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वच्छ एवं सुंदर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। अभियान के माध्यम से लोगों से



अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने तथा अन्य लोगों को भी

स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने की अपील की गई।